Subject :- Sociology Date :- 09/07/2020
Class :- 12th
Topic :- क्षेत्रवाद के परिणाम एवं निराकरण हेतु सुझाव
By :- श्यामानंद चौधरी, अतिथि शिक्षक, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा

online Study Material No :- (108)

क्षेत्रवाद का प्रभाव कभी भी स्वस्थकर नहीं होता। अतः इसके प्रभावों को दुष्परिणाम कहना अनुचित नहीं प्रतीत होता है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम निम्नांकित है :—

1) संकीर्ण नेतृत्व का विकास :— क्षेत्रवाद के कारण ऐसे स्वार्थी और संकीर्ण विचार वाले नेताओं कि संख्या में वृद्धी होती है, जो क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर अपने स्वार्थों की पूर्ती में लगे रहते है, ऐसे स्वार्थी नेता समय - समय पर आंदोलनों तथा प्रदर्शनों का आयोजन करके एक क्षेत्र विशेष में अपने महत्व को बढ़ाते है, वे जनता का नेतृत्व कर सरकार पर दबाव डालने और व्यक्तिगत हीतों की पूर्ति में लग जाते हैं। बार-2 आंदोलन और तोड़फोड़ आर्थिक नाकेबंदी कि क्रियाओं को करते रहने के कारण उस क्षेत्र विशेष कि प्रगती रुक जाती है।

3) राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास मे बाधक :— क्षेत्रवाद के कारण प्रत्येक क्षेत्र के निवासी अधिकाधिक अधिकारों तथा सुविधाओं को लेकर एक दुसरे के विरोधी बन जाते है, धीरे-2 क्षेत्र बाद कि मांग की भावना के कारण केन्द्र सरकार पर लोगों की निष्ठा कम होने लगती है, ऐसी परिस्थिती में व्यवस्था और प्रशासण एक समस्या का रूप ले लेता है, और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकता खंडीत होती है,

4) क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा :— क्षेत्रवाद के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच एक दुसरे के प्रति विद्वेषपूर्ण मनोवृत्ति उत्पन्न होती है, यदि किसी क्षेत्र के निवासी क्षेत्रवाद के आधार पर कुछ विशेष सुविधाओं कि मांग को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन करते है तो दुसरे क्षेत्र के लोग उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते है, फलस्वरुप क्षेत्रीय तनाव में वृद्धी होती है अभी हाल ही में बिहार के हाजीपुर के रेलवे के एक (zonal office) बनाने कि घोषणा जब रेलमंत्री नीतीश कुमार ने की तब ममता बनर्जी और बंगाल के अन्य नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन होना शुरु हो गया ऐसी परिस्थिती मे बिहार एवं बंगाल के संबंधों मे तनाव उत्पन्न हो गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरुप बिहार मे भी उग्र प्रदर्शन होना शुरु हो गया। क्षेत्रीयता के आधार पर कारखानों का निर्माण, विश्वविद्यालयों कि स्थापना, सिमारेखा का विवाद, प्राकृतिक साधनों का बंटवारा तथा सरकारी अनुदान को लेकर विभिन्न समय में, विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार

Scanned with CamScanner

②

विवाद बढ़ते जा रहे हैं उससे क्षेत्रीय तनावों कि स्थिती अत्यन्त गंभीर बनती जा रही है।

5) प्रगति में बाधा :-

क्षेत्रवाद के कारण उत्पन्न उग्र आंदोलन आर्थिक प्रगती के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्षेत्रवाद की भावना से प्रभावित क्षेत्र में उग्र आंदोलन और तोड़-फोड़ के कारण उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। साथ ही आंदोलन को दबाये रखने के लिये शांती व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रशासनिक कार्य पर खर्च बढ़ जाता है। क्षेत्रवाद के फलस्वरूप सरकार को अक्सर ही क्षेत्र वाद से प्रभावित क्षेत्रों को अधिक आर्थिक सुविधाएं देनी पड़ती है। फलस्वरूप कुछ क्षेत्र समृद्ध बनते जाते हैं जबकी अनुशासित जीवन व्यतीत करनेवाले क्षेत्रों के लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

निराकरण के लिये सुझाव :-

क्षेत्रीयवाद की समस्या से निपटने के लिये कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं जो निम्नांकीत है :-

1) राष्ट्रीय हीत को ध्यान में रखकर नीति निर्धारण करना और दबाव में आकर उनका परिवर्तन न करना :-

क्षेत्रवाद की समस्या के निवारण के लिये सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है की सरकार राष्ट्रीय हीतों को ध्यान में रखकर नीती का निर्धारण करें। न कि किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर। यदि मंत्री और सरकारी अधिकारी अपने-2 क्षेत्र को अधिक लाभ प्रदान करने के लिये योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे तो इससे इससे क्षेत्रवाद कि समस्या और गंभीर हो जायेगी। यह भी आवश्यक है कि एक बार एक बार राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारण हो जाने के बाद क्षेत्रीय दबाव में इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न लाया जाय।

2) सभी क्षेत्रों के विकास के लिये कार्यक्रम तैयार करना किन्तु पिछड़े क्षेत्रों के लिये विकास पर अधिक बल देना :-

विकास कार्यक्रम का निर्धारण इस ढंग से किया जाना चाहीये जिससे सभी क्षेत्रों का विकास हो। इससे क्षेत्रीय असंतोष कम होगा। साथ ही सरकार को चाहीये की अविकसित

क्षेत्रों के विकास पर अधिक बल दें। ऐसा करने पर क्षेत्र के पिछड़ेपन के प्रश्न को लेकर जो असंतोष उत्पन्न होता है, कुछ हद तक कम होगा।

3) क्षेत्रीय नाम पर बने राजनैतिक दलों को मान्यता न देना :—
क्षेत्रीय नाम पर बने राजनैतिक दल क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं, अतः वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि क्षेत्रीय नाम पर बने राजनैतिक दलों को मान्यता न ही देना चाहिये। क्षेत्र के नाम पर बनकर झारखंड पार्टी ने क्षेत्रीय भावना उत्पन्न कर बिहार राज्य का विभाजन करा दिया। अतः क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को मान्यता समाप्त करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह कार्य कुछ कठीन अवश्य है, किन्तु राष्ट्रीय हित में अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि ये क्षेत्रीय राजनैतिक दल क्षेत्रीयता की भावना को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय एकता को दुर्बल बनाते हैं।

S. N. Choudhary
Marwari College
Darbhanga

Scanned with CamScanner